



अपने घर का सच जानने के लिए भूकंप का इंतजार मत कीजिए

अब जयपुर, अलवर, भिवाड़ी भूकंप के हाई रिस्क जोन में

जयपुर। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने भूकंप को लेकर देश के नए रिस्क घोषित किए हैं। अब जयपुर, अलवर, भिवाड़ी हाई रिस्क जोन में हैं। इस जोन के शहरों में 5 से 6 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आ सकते हैं। जयपुर 2016 तक माइल्ड डेमेज रिस्क जोन-2 में था। अब जयपुर, भिवाड़ी और अलवर को जोन 4 में शामिल किया है। 2016 तक बीकानेर जोन 3, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जोन 2 में थे। वहीं, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के ओर से नया नक्शा जारी होने के बाद जो शहर हाई रिस्क जोन में वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नए नियमों के बनाने होंगे।

- अब जयपुर भूकंप के हाई रिस्क जोन में
- जयपुर की अधिकतम RCC इमारतें भूकंप रोधी नहीं
- कल अगर कुछ हो जाए तो क्या आप रिस्क लेने को तैयार हैं? अगर नहीं तो आज ही Structural Engineer से संपर्क करें या केडिया सेजस्थान कॉल करें
- बहुत से लोग मानते हैं कि RCC इमारतें अपने आप सुरक्षित होती हैं। यह एक खतरनाक भ्रम है।

भूकंप रोधी क्षमता इन बातों पर निर्भर करती हैं :

- स्ट्रक्चरएल डिज़ाइन
- कॉलम बीम
- कंपन भार गणना
- डक्टाइल डिटेलिंग (IS 13920)



केडिया होम्स के हर प्रोजेक्ट में होती है भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शन वाली
बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े फ्लैट छोटी छोटी प्राइस में



कोठी: सिर्फ ₹47000/-
Sq Ft

फ्लैट: सिर्फ ₹40000/-
Sq Ft

FIXED PRICE & RENTAL

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	FIXED PRICE	PROPOSED RENTAL (AFTER POSSESSION)
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 LACS	22,000
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 LACS	25,000
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 LACS	28,000
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 CRORE	30,000
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.10 CRORE	40,000
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.50 CRORE	50,000

31 दिसम्बर को 10 लाख रेंट बढ़ेगी



KEDIA
सेजस्थान
KOTHI & WALK-UP APARTMENT

अजमेर रोड, जयपुर

पजेशन: 31 दिसम्बर 2025 से शुरू

KEDIA®

1800-120-2323

78770-72737

info@kedia.com

www.kedia.com

www.rera.rajasthan.gov.in
RERA No. RAJ/P/2023/2387

SCAN QR FOR
• LOCATION
• ROUTE MAP
• SITE 360 TOUR
• E-BROCHURE
• WALKTHROUGH



*T&C Apply

विचार बिन्दु

कल्पना विश्व पर शासन करती है। –नेपोलियन

राजस्थान में बढ़ता प्रदूषण: नियंत्रण के उपाय एवं तात्कालिक आवश्यकता

राजस्थान में बढ़ता प्रदूषण आज केवल पर्यावरणीय चुनौती नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर सीधा खतरा बन चुका है। राज्य के कई शहर लगातार खराब वायु गुणवत्ता, बढ़ती धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और जल-मिट्टी के प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर जैसे महानगर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें सतत प्रदूषित शहरों की सूची में चिह्नित किया गया है। कई निगरानी केन्द्रों के आँकड़ों में पीएम 1० और पीएम २.५ का स्तर अक्सर मानक सीमा से कहीं अधिक दर्ज होता है, जिससे वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी तक पहुँच जाती है। एक ताज़ा अध्ययन में राजस्थान के पाँच प्रमुख शहरों में कणीय प्रदूषकों के ऊँचे स्तर के कारण साँस और हृदय संबंधी रोगों में वृद्धि की आशंका जताई गई है, भले ही कुछ गैसीय प्रदूषक (जैसे एसओ२, एनओ२) औद्योगिक मानकों के भीतर हों। इससे साफ है कि धूल और सूक्ष्म कण वर्तमान संकट की मुख्य वजह बन चुके हैं।

राजस्थान की शुष्क-अर्धशुष्क जलवायु के कारण स्वाभाविक रूप से धूल का स्तर अधिक रहता है, लेकिन तेज शहरीकरण, वाहन दबाव और निर्माण गतिविधियों ने इस धूल को खतरनाक प्रदूषण में बदल दिया है। खनन क्षेत्र और औद्योगिक क्लस्टर, विशेषकर जोधपुर व पाली आदि, गंभीर प्रदूषण सूचकांक के दायरे में आए हैं और वहाँ की हवा व आसपास के इलाकों की मिट्टी-जल पर इसका प्रभाव दिख रहा है। वाहन उत्सर्जन, सड़कों पर उड़ती धूल, निर्माण-ध्वस्तोकरण के मलबे, औद्योगिक धुआँ और कचरा जलाना मिलकर शहरों की वायु गुणवत्ता को बिगाड़ रहे हैं। दूसरी ओर, नदियों-तालाबों में औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और रसायनों के बहाव से जल प्रदूषण को रोकने के लिए अलग से कड़े प्रबंधन की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्य स्तर पर जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियमों में संशोधन किए गए हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दमा, एलर्जी, सीओपीडी, हृदय रोग और बच्चों-बुजुर्गों में फेफड़ों की क्षमता में कमी जैसे जोखिम स्पष्ट रूप से बढ़ रहे हैं। उच्च पीएम१० और पीएम२.५ वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने से फेफड़ों में सूक्ष्म कण जमा होकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की संभावना भी बढ़ा सकते हैं। धूल और रासायनिक प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है, जबकि दूषित जल सिंचाई के माध्यम से फसलों और फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर मानव स्वास्थ्य पर 'धीमा जहर' जैसा प्रभाव छोड़ सकता है। समाज स्तर पर प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य व्यय, कार्यक्षमता में कमी और जीवन की गुणवत्ता गिरने से आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है, जिसका उल्लेख स्वच्छ वायु कार्यक्रम से जुड़े मूल्यांकन अध्ययनों में किया गया है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु, जल और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी, अनुमति, निरीक्षण और मानकों के अनुपालन का काम कर रहा है, साथ ही ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से उद्योगों की निगरानी को मजबूत किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत अलवर,

प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रशासन, उद्योग और नागरिक-तीनों स्तरों पर ठोस कार्रवाई आवश्यक है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए प्रदूषण नियंत्रण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि जल-संकट, कृषि, पर्यटन और लोक-स्वास्थ्य से जुड़ा विकास का प्रश्न है; इसलिए योजनाओं में क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल शहरों-गाँवों की सोच को केंद्रीय स्थान देना होगा।

है, किंतु क्रियान्वयन में कमी के कारण प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक बना हुआ है। उद्योगों को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज और फ्ल्यू गैस ट्रीटमेंट अनिवार्य करने के बावजूद कई इकाइयाँ मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, जिसके लिए सख्त निरीक्षण और दंड की आवश्यकता है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रशासन, उद्योग और नागरिक-तीनों स्तरों पर ठोस कार्रवाई आवश्यक है। शहरों में सड़क धूल को नियंत्रित करने के लिए नियमित मैकेनिकल स्वैपिंग, निर्माण स्थलों की बैरिकेडिंग व कवरींग, ग्रीन बेल्ट विकास और खुले भूखण्डों पर वृक्षारोपण जैसे उपाय प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं, जिन पर स्वच्छ वायु योजनाओं में जोर दिया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में ईंधन परिवर्तन (कोयले से स्वच्छ ईंधनों की ओर), एम्पलूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, फ्ल्यू गैस ट्रीटमेंट और ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित करना होगा, जैसा कि जोधपुर औद्योगिक क्लस्टर की कार्ययोजना में सुझाया गया है। नगर निकाय स्तर पर कचरा प्रबंधन में ख़ोत पर कचरा पृथक्करण, वैज्ञानिक लैंडफिल, कंपोस्टिंग और खुले में कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है। खनन क्षेत्रों में धूल नियंत्रण के लिए पानी छिड़काव, ग्रीन कवर और परिवहन मार्गों पर नियंत्रण जैसे उपाय अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि थार मरुस्थल के निकट खनन प्रदूषण को कई गुना बढ़ा रहा है। जल प्रदूषण रोकने हेतु नदियों के किनारे प्रवेश ज़ोन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का विस्तार और औद्योगिक अपशिष्टों पर जीओएस ट्रेकिंग अनिवार्य होनी चाहिए। इन उपायों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को बजट आवंटन बढ़ाना होगा, साथ ही कॉर्पोरेट सीएसआर फंडिंग को प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित करना चाहिए।

लंबे समय में प्रदूषण नियंत्रण तभी सफल होगा जब नागरिक स्वयं निजी वाहनों के अत्यधिक उपयोग से बचकर सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और साइकिलिंग को अपनाएँ तथा स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण और जल-मिट्टी संरक्षण अभियानों से जुड़ें। स्कूल-कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा और 'ग्रीन क्लब' जैसी पहलें युवाओं में स्वच्छ हवा के अधिकार और जिम्मेदारी दोनों का बोध पैदा कर सकती हैं, जो भविष्य की नीतियों पर सकारात्मक दबाव बनाएँगी। राजस्थान जैसे राज्य के लिए प्रदूषण नियंत्रण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि जल-संकट, कृषि, पर्यटन और लोक-स्वास्थ्य से जुड़ा विकास का प्रश्न है; इसलिए योजनाओं में क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल शहरों-गाँवों की सोच को केंद्रीय स्थान देना होगा। जोधपुर जैसे शहर, जहाँ सीमेंट और निर्माण उद्योग प्रमुख हैं, वहाँ विशेष रूप से धूल नियंत्रण और हरित ऊर्जा पर जोर देकर मॉडल स्थापित किया जा सकता है। यदि नीति, तकनीक और जनचेतना तीनों मिलकर काम करें, तो राजस्थान की हवा, पानी और मिट्टी को फिर से स्वस्थ दिशा में मोड़ा जा सकता है। समय आ गया है कि हम प्रदूषण की विकास का दुरुमन न मानें, बल्कि इसे नियंत्रित कर सतत प्रगति का आधार बनाएँ। राजस्थान की रेतली धरती पर फिर से हरियाली और स्वच्छता का स्वप्न साकार करने का संकल्प ही हमारा वास्तविक कर्तव्य है।

–अतिथि संपादक,

अविनाश जोशी,

वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सलाहकार

		
राशिफल शनिवार 20 दिसम्बर, 2025		
पौष मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शनिवार, विक्रम संवत २०८२, मूल नक्षत्र रात्रि १:२२ तक, गंड योग सायं ४:१७ तक, किस्तुघ्न करण रात्रि ८:१२ तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।		
ग्रह स्थिति: सूर्य- धनु, चन्द्रमा-धनु, मंगल- धनु, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।		
आज ज्वालामुखी योग रात्रि १:२२ तक है। शुक्र मूल धनु में प्रात: ७:४५ पर प्रवेश करेगा।		
श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ ८:३२ से ९:५० तक, चर १२:२४ से १:४१ तक, लाभ-अमृत १:४१ से ४:१६ तक।		
राहूकाल: ९:०० से १:३० तक। सूर्योदय ७:१५, सूर्यास्त ५:३३ तक		

			
मेघ	सिंह	धनु	
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।	मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।	
			
वृष	कन्या	मकर	
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से मतभेद हो सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।	घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।	
			
मिथुन	तुला	कुंभ	
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।	व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	
			
कर्क	वृश्चिक	मीन	
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।	आर्थिक कार्यों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।	व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	

क्या दवा माफिया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को निष्फल करने में लगा है?



रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

देश में स्वास्थ्य-सुधार और सस्ती दवाओं की उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एक ऐतिहासिक पहल मानी गई है। यह योजना उस समय ऐसे वातावरण में शुरू हुई थी, जब भारत में दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं और गरीब-मध्यमवर्गीय परिवारों पर चिकित्सा व्यय एक असहनीय बोझ बन चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूल भावना थी – दवा एक विलासिता नहीं, बल्कि हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है।

लेकिन जिस विचार और संवेदनशीलता के साथ यह योजना आकार ली थी, वह आज गंभीर चुनौतियों से घिरी दिखाई देती है। एक तरफ जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सरकार गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का दावा करती है, दूसरी ओर बाजार में ८०-९० प्रतिशत छूट पर मिलने वाली संदिग्ध जेनेरिक दवाओं की बाढ़ ने पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह संयोग मात्र नहीं लगता; बल्कि एक संगठित प्रयास प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य जन औषधि योजना की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाना है।

जेनेरिक दवाओं की अंधाधुंध छूट – संदेह की पहली कड़ी आज लगभग पूरे देश में यह दृश्य

आम हो चुका है कि मेडिकल स्टोर एमआरपी से ८० या ९० प्रतिशत कम कीमत पर दवाईयाँ देने का दावा करते हैं। सवाल उठता है –

यदि दवा इतनी सस्ती उपलब्ध हो सकती है, तो फिर एमआरपी पर इतना भारी-भरकम मूल्य क्यों अंकित किया जाता है?

क्या यह व्यापारिक असंतुलन है, या एक सुनियोजित धोखाधड़ी? दिवाली के पटाखों की तरह, जिनका एमआरपी और वास्तविक मूल्य में भारी अंतर होता है, दवाओं का ऐसा व्यवहार गहरी चिंता का विषय है। लेकिन पटाखों से भिन्न, दवा कोई मनोरंजन का साधन नहीं – यह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा है। इस क्षेत्र में इस तरह का अव्यवस्थित मूल्य-निर्धारण न केवल अनैतिक है बल्कि खतरनाक भी है।

जब सरकारी केंद्रों पर निजी दवाओं की चुसपैठ होने लगे

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के केंद्रों पर केवल सरकार द्वारा आपूर्ति की गई दवा ही बेचे जाने का प्रावधान है। लेकिन हाल के महीनों में लगातार शिकायतें सामने आई हैं कि कई जन औषधि केंद्रों पर निजी जेनेरिक दवाएँ बेची जा रही हैं – वह भी ऐसी दवाएँ जो किसी प्रकार की गुणवत्ता जाँच के मानक पर खरी नहीं उतरती।स्थिति यह है कि – ब्रांड का मालिक कोई और, निर्माता कोई और, मार्केटर कोई तीसरा, और दुकानदार पूरी व्यवस्था से अनभिज्ञ। ग्राहक प्रधानमंत्री के नाम पर भरोसा करके जन औषधि केंद्र पर पहुँचता है, लेकिन उसे ऐसी दवा धमा दी जाती है जिसका न खोत स्पष्ट है और न गुणवत्ता। यह न केवल योजना की भावना का अपमान है, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है।

प्रधानमंत्री की भावना, प्रशासन की जिम्मेदारी और व्यवस्था की चुक

यह उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत में बीफार्मा- और डीफार्मा- युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी जुड़ा था। सरकार ने नाममात्र की राशि लेकर दुकानों का पूरा ढांचा उपलब्ध कराया – कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, दवा स्टॉक और केंद्रीकृत सप्लाई।

मैं स्वयं उदयपुर में इस योजना के प्रारंभ का साक्षी रहा हूँ। उस समय राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, जो तब दिल्ली में फार्मा विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी थे, ने अत्यंत ईमानदार नीयत और कठोर गुणवत्ता मानकों के साथ यह परियोजना आगे बढ़ाई थी। लेकिन आज जो हालात बन गए हैं, वे उनकी मूल भावना के बिल्कुल विपरीत हैं। जिला ड्रग कंट्रोल कार्यालयों की उदासीनता व अकर्मण्यता इस समस्या को और गहरा कर रही है। और उनकी मिलिभगत से इंकार नहीं किया जा सकता।

दवा माफिया का फैलता प्रभाव – संगठित नेटवर्क का संकेत

सवाल यह है कि निजी कंपनियों की दवाएँ जन औषधि केंद्रों तक पहुँच कैसे रही हैं? इसका उत्तर स्थानीय स्तर पर फैली मिलीभगत में छिपा है। कुछ शहरों में तो यह भी देखा गया है कि – एक ही व्यक्ति ने २०-२५ जेनेरिक दवाओं की दुकानों का नेटवर्क खड़ा कर रखा है, जहाँ – अयोग्य स्टाफ, दवा पढ़ने तक का ज्ञान नहीं, ग्राहक पर गलत दवा थोपने की प्रवृत्ति, और अधिक मुनाफे के लिए संदिग्ध उत्पादों का व्यापार – जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। यह केवल प्रशासनिक चुक नहीं, बल्कि एक गहरे जड़ जमाए माफिया-तंत्र की ओर संकेत है। यह केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं – यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। दवाओं की दुनिया में कोई भी गलती मजक नही होती। गलत सॉल्ट, गटिया गुणवत्ता, या अप्रमाणित निर्माण-स्थल वाली दवाएँ

मरीज की हालत सुधारने के बजाय बिगाड़ देती हैं। जब प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जैसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को ही कमजोर किया जाने लगे, तो यह समझना होगा कि समस्या केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रश्न नहीं है –

यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सुरक्षा का मुद्दा है। सरकार को क्या करना चाहिए? – स्पष्ट और कठोर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता

इस स्थिति में सिर्फ सलाह या अपील पर्याप्त नहीं। अगर कठोर प्रशासनिक और संरचनात्मक कदम आवश्यक हैं:–

१. जन औषधि केंद्रों पर निजी जेनेरिक दवाओं की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

किसी भी दुकान पर निजी दवा पाए जाने पर उसका लाइसेंस तत्काल निलंबित होना चाहिए। यह योजना तभी सुरक्षित रह सकती है, जब इसकी परिधि में निजी आपूर्ति शून्य हो।

२. एमआरपी को फैक्ट्री स्तर पर नियंत्रित किया जाए

दवाओं का एमआरपी उत्पादन लागत के अनुरूप और पारदर्शी हो। बाजार में ८० प्रतिशत डिस्काउंट का खेल तभी खत्म होगा, जब एमआरपी वास्तविकता आधारित हो।

३. सप्लाई चेन का रियल-टाइम डिजिटलीकरण

सरकारी पोर्टल पर हर दवा की एंट्री, निकासी, बैच नंबर और खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड अनिवार्य हो। यह पारदर्शिता निजी दवाओं की चुसपैठ स्वत: रोक देगी।

४. जिला ड्रग कंट्रोल विभाग की जवाबदेही तय हो

निरीक्षण, कार्रवाई और शिकायतों का सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड जारी हो। जहाँ लापरवाही दिखे – वहाँ तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई हो।

भांकरोटा हादसे का एक वर्ष

कई परिवारों को दे गया जीवनभर के जख्म

आज भांकरोटा हादसे को एक वर्ष बीत चुका है, किन्तु उस की भयावहता को याद कर आज भी सिरहाने महसूस होती है। २० दिसम्बर, २०२४ के दिन की वो स्याह, सर्द अलसुबह हमसे हमारा सच कुछ छीन ले गई। समय के पाबंद हमारे पापा अपनी नियमित दिनचर्यानुसार गुरुवार, १९ दिसम्बर को प्रात: पांच बजे घर से अजमेर रोड स्थित कृषि फार्म के लिए निकले थे २० दिसम्बर की सुबह लौटना था पर वे कभी नहीं

लौटे और हमें दे गए जीवन भर का इंतजार। जो व्यक्ति जीवन भर किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा उनके शव की शिनाखा डीएनए, कार के चैसिस से करनी पड़ी। हमारे पिता, हमारे पथ प्रदर्शक एवं आदर्श जो अपने समस्त सेवा काल में व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते रहे, अंत में उसी व्यवस्था की भेंट चढ़ गए, यह बात उग्रभर कचोटती रहेगी।

हमारे पिता करणी सिंह राठौर एक ईमानदार, दबंग, तत्परता से निर्णय लेने

वाले, संजोदा और कर्मठ आईएएस ऑफिसर थे। श्रीगंगानगर और अजमेर कलेक्टर रहते हुए आम आदमी एवं किसानों के लिए एतिहासिक कार्य करके अत्यंत दूर दराज के इलाकों में रेवन्यू शिबिर लगाकर किसानों को जमा बंदि्यां सुलभ करवाई और वर्षों के दबे उनके अधिकार दिलवाकर उनके कर्कों का निवारण किया। अजमेर डिस्कॉम और जयपुर नगरपरिषद में कार्य करते हुए उन्होंने कर्मचारियों और आमजन सभी के कल्याण के लिए

ऐतिहासिक फैसले लिये और उन्हें तत्परता से लागू करवाया था।

बिल्कुल अलग तरह से लोगों के लिए जीने वाले हमारे पिता अपने आखिरी समय में भी इस व्यवस्था की खामियों की भेंट चढ़ने वालों की कतार में सबसे आगे खड़े थे। काश व्यवस्था के जिम्मेदार उस दर्द का एक अंश भी समझ पाए जो हम भोग रहे हैं २० दिसम्बर, २०२४ की सुबह से। काश इस तरह के भर उठाड़ने वाले हादसे किसी की लापरवाही का

–सुमन राठौर

धोधलिया गांव में लेपर्ड ने दो युवकों पर हमला किया

चूरू, (निसं)। जिले के रतननगर थाना क्षेत्र के गांव धोधलिया में शुक्रवार सुबह खेत में सरसों की फसल में छिपकर बैठे एक लेपर्ड ने दो युवकों पर हमला कर दिया। हमले में एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई है। घायल युवकों को डीबी अस्पताल

■ **खेत में सरसों की फसल में छिपकर बैठे था, खेत में काम कर रहे युवकों पर किया हमला**

पहुँचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि घटना सुबह करीब ७:३० बजे की है, जब धोधलिया निवासी २७ वर्षीय राकेश और २५ वर्षीय गोविंदराम अपने खेत में सरसों की फसल में पानी की लाइन बदलने गए थे। वे अलसुबह करीब चार बजे खेत पहुंचे थे। इस दौरान तेंदुए ने गोविंद और राकेश पर हमला बोल दिया, जिससे राकेश के सिर में गंभीर चोट आई। युवकों के शोर मचाने पर आस-पास के खेतों से ग्रामीण मौके



घायल युवक को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया।

पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत दोनों घायलों को निजी वाहन से डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया। अस्पताल में मेडिकल कॉलेज प्राचाय डॉ. एम.एम.

पुकार के नेतृत्व में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका उपचार किया। गांव के लोगों ने बताया कि तेंदुए के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है।

विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी को लेकर किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन

चूरू, (निसं)। ग्राम बालरासर आधुणा के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग के नेतृत्व में शुक्रवार को वोल्टेज कम आने, बार-बार ट्रिपिंग को लेकर और ग्राम बालरासर आधुणा में जीएसएस स्वीकृत करवाने को लेकर जोधपुर डिस्कॉम निगम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद अधीक्षण अभियंता आरपी वर्मा ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। यूनियन के जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग ने अनुवाई में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा।

■ **किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा।**

ज्ञापन में बताया कि कम वोल्टेज आने व बार बार ट्रिपिंग के चलते किसानों के कुओं की मोटरें जलने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने से किसानों की फसलें खराब हो रही है। जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि अधीक्षण अभियंता ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर आज ही

पीथीसर जीएसएस पर फीडर अलग करने, घंटेले से अलग विद्युत लाईन खिंचवाने तथा बालरासर आधुणा में नया जीएसएस स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव बनाने की बात कही। इस दौरान किसानों के प्रतिनिधि मण्डल में भारतीय किसान यूनियन के ओमप्रकाश, जयलाल, सुनील, सुशील, सीताराम, महेंद्र, राम्रूम, ओमप्रकाश, दीपचंद, भगताराम, सुरेश कुमार, जगदीश, सुभाष, बाबूलाल, भालाराम, ब्रक्कण, राज्रराम, धर्मचंद और मांगीलाल सहित बड़ी संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

उर्स मेले के लिए विशेष रेल सेवाओं का संचालन

अजमेर, (निसं)। रेलवे द्वारा उर्स मेले के दौरान अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु बरेली-दौराई (अजमेर)-बरेली अनारक्षित स्पेशल एवं आजमगढ़-अजमेर-आजमगढ़ उर्स स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

गाड़ी संख्या ०४३९८ बरेली-दौराई (अजमेर) अनारक्षित स्पेशल २२ से २८ दिसंबर तक प्रतिदिन बरेली से शाम ४.५० बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह ७.५५ बजे दौराई पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या ०४३९७ दौराई-बरेली स्पेशल २३ से २९ दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर १२.१५ बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह ६.४५ बजे बरेली पहुंचेगी।

यह रेल सेवा मार्ग में दिल्ली, जयपुर, फुलेरा, किशनगढ़ एवं अजमेर

५. निजी कंपनियों की अवैध सप्लाई पर अपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएँ

यह महज नियम उल्लंघन नहीं – यह सरकारी योजना को निष्प्रभावी करने की साजिश है। इस पर दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए।

६. दवा बिक्री के लिए योग्य फार्मासिस्ट अनिवार्य हों

दवा जनता की जान से जुड़ा विषय है;

अयोग्य स्टाफ के हाथों इसे सौंपना अपराध की श्रेणी में आना चाहिए।

७. अमानक या नकली दवा के कारोबार में लिप्त या उनको संरक्षण देने वालों या उनको बचाने वालों को मृत्युदंड का कानून बनाना चाहिए। क्युकी वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को बचाना केवल सरकार नहीं – पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यह योजना उस समय एक आशा का दीपक बनी थी, जब देश का आम नागरिक दवा के लिए आर्थिक संघर्ष झेल रहा था।

आज जब निजी कंपनियों की मिलीभगत, प्रशासनिक लापरवाही और माफिया-तंत्र इस योजना की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार निर्णायक कदम उठाए और व्यवस्था में कठोर पारदर्शिता सुनिश्चित करे।

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना केवल सस्ती दवाओं की योजना नहीं है – यह जनता की स्वास्थ्य-सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वास का प्रतीक है। इसे बचाना, सुदृढ़ करना और माफिया-प्रभाव से मुक्त रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

–रोटेरियन सुनील दत्त

गोयल,

महानिदेशक, इम्पीरियल

चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।



राहुल गांधी ने जी राम जी स्कीम पर प्रहार ही प्रहार किये

‘सरकार ने केवल नाम ही नहीं बदला मनरेगा का, बल्कि अधिकार व मांग पर आधारित स्कीम को एक “राशन” स्कीम बना दिया, जिसका नियंत्रण दिल्ली के हाथ में है’

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 दिसंबर। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि 20 साल पुरानी मनरेगा योजना को एक दिन में नष्ट कर दिया गया है, उन्होंने नए वीबी जी राम जी विधेयक को “गांव विरोधी” करार दिया।

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा, वीबी जी राम जी मनरेगा का काया पलट नहीं है, बल्कि “बीती रात, मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल की मनरेगा को खत्म कर दिया...” उन्होंने कहा, “यह अधिकार आधारित, मांग से प्रेरित गारंटी को नष्ट करता है और इसे एक राशनिंग योजना में बदलता है, जिसे दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। इसका डिजाइन राज्य और गांव विरोधी है।”

विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों की सशक्त किया था और उन्हें मोल-भाव की ताकत दी थी।

- राहुल के अनुसार, मनरेगा ने ग्रामीण मेहनतकश को “बारगेनिंग पावर” (बातचीत कर अपनी बात मनवाने का अधिकार) दिया था। सरकार ने “बारगेनिंग पावर” खत्म कर दिया।
- राहुल के अनुसार, कोविड के समय हमने देखा था, जब इकॉनमी ठप्प हो गई थी, मनरेगा ने करोड़ों को भूख व कर्ज से बचाया था। पर, अब कितना काम उपलब्ध होगा, उसकी सीमा बांध कर सरकार ने काम न देने का नया बहाना दे दिया सरकार को।
- राहुल गांधी ने अंत में सरकार को चुनौती दी कि, मनरेगा गरीबी हटाने व ग्रामीण जनता के सशक्तिकरण का विश्व में सबसे सफल प्रोग्रामों में से एक है और वे सरकार को गरीबों के अंतिम हथियार को खत्म नहीं करने देंगे तथा सभी राज्यों में पंचायत स्तर तक आंदोलन खड़ा कर, सरकार को बाध्य करेंगे कि वह जी जी राम जी विधेयक वापस ले।

गांधी ने कहा, “जब (ग्रामीण लोगों को) वास्तविक विकल्प मिले तो शोषण और परेशानी से हो रहे पलायन में कमी

के साथ हुआ। यही वो ताकत है, जिसे यह सरकार तोड़ना चाहती है।”

लोकसभा में विपक्षी नेता ने कहा कि काम की सीमा तय कर और उसे अस्वीकार करने के और तरीके बनाकर, वीबी जी राम जी विधेयक ग्रामीण गरीबों को जो एकमात्र ताकत मिली थी, उसे कमजोर कर देता है।

गांधी ने कहा, हमने देखा कि कोविड के दौरान मनरेगा का क्या फायदा हुआ। जब अर्थव्यवस्था बंद हो गई और आजीविका संकट में आ गई, तो इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डबने से बचाया।”

उन्होंने कहा कि इसने महिलाओं को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया। हर साल, महिलाएं आधे से अधिक व्यक्ति दिवसों में योगदान करती थीं।

उन्होंने लिखा, “जब आप एक रोजगार योजना को राशन करते हैं, तो सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन श्रमिक और गरीब तथा ओबीसी समुदाय बाहर हो जाते हैं।” (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव 25 अप्रैल तक होंगे

जयपुर, 19 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और परिसीमन की कार्रवाई व प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एसएलपी

- सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

को खारिज कर दिया है। जस्टिस जायमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने ये आदेश संयम लोढ़ा की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) पर दिए।

एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 14 नवंबर 2025 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरा करने और ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘विभागीय पदों पर आरएएस भर्ती-2023 में नियुक्ति नहीं दें’

जयपुर, 19 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 में विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने रोहित कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते

- हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगाई।

हुए यह आदेश दिया। अदालत ने माना कि प्रकरण में विभागीय पदों पर जातिगत आरक्षण का बिंदु विचारणीय है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा इन पदों पर नियुक्ति दी जाती है तो पक्षकारों के हित प्रभावित होंगे।

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि आरएएस भर्ती-2023 में कुल पदों में से 12.5 फीसदी पद अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे गए थे। आरपीएससी की ओर से भर्ती का परिणाम जारी करते समय, विभागीय पदों पर सामान्य कट ऑफ ही जारी की गई, जबकि आयोग को विभाग के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए अलग से कट ऑफ जारी करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करने से याचिकाकर्ताओं को जातिगत आरक्षण से वंचित किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

5 राज्यों को नए चीफ जस्टिस मिलेंगे

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने 5 वरिष्ठ जजों की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर नियुक्ति की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने गुरुवार को उत्तराखंड, मेघालय, झारखंड, सिक्किम और पटना उच्च न्यायालयों में पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दिये जाने की सिफारिश की है। महत्वपूर्ण न्यायिक नेतृत्व से सम्बन्धित यह कदम न्यायिक ढांचे को मजबूत करने और सेवानिवृत्तियों के बाद निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कोलीजियम के इन निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से जारी किया गया और औपचारिक कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया।

यह सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, सूर्यकांत के कार्यकाल के दौरान लिया गया एक महत्वपूर्ण न्यायिक नेतृत्व निर्णय है, जिन्होंने नवम्बर 2025 में पदभार ग्रहण किया

- सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत का यह पहला बड़ा “लीडरशिप” फैसला है।
- उन्होंने उत्तराखंड, मेघालय, झारखंड, सिक्किम और पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए नामों की सिफारिश की ताकि समय रहते नियुक्ति हो जाए और न्यायिक कार्यों में निरंतरता बनी रहे।
- जिन न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई है, वो हैं, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जस्टिस रेवती पी मोहिते डेरे, जस्टिस एम एस सोनक, जस्टिस मुहम्मद मुश्ताक, जस्टिस संगम कुमार साहू।

था और अपने पूर्ववर्ती से कार्यभार संभालने के बाद, न्यायपालिका की कार्यक्षमता और संविधानिक अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की दिशा में काम कर रहे है। कोलीजियम ने हाईकोर्ट के इन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है:

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय

में सेवा दे रहे हैं, को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। पदोन्नति की यह सिफारिश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने की संभावना को देखते हुए की गई है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवती पी. मोहिते डेरे को

मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। उनकी नियुक्ति मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के कारण की गई है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। यह निर्णय जनवरी 2026 में रिक्त हो रहे पद को देखते हुए लिया गया है।

केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिशें पूर्वी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी न्यायिक क्षेत्रों में नेतृत्व के संतुलित बदलाव को दर्शाती है।

जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ से मिले राहुल

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ स्कोलज के साथ मुलाकात कर वैश्विक मामलों, व्यापार और बदलती दुनिया में भारत-जर्मनी संबंधों को

- दोनों नेताओं ने बदलते वैश्विक माहौल में भारत व जर्मनी के संबंध मजबूत करने पर चर्चा की।

मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। गांधी ने बर्लिन के हर्टी स्कूल में छात्रों, विद्वानों और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए बदलते विश्व में नेतृत्व, लोकतंत्र और वैश्विक जिम्मेदारी पर चर्चा की। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक स्थितियों के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर अपने विचार भी रखे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और राजनीतिक अनुभवों को भी साझा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस बार रविवार को पेश होगा केन्द्रीय बजट

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर। आगामी एक फरवरी को रविवार होने के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 का बजट लोक सभा में उसी दिन पेश किया जाएगा।

रिजिजू ने संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद संसद परिसर

- असल में बजट हर बार एक फरवरी को पेश होता है इस बार एक फरवरी को रविवार है और रविवार को संसद में अवकाश होता है। पर, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, रविवार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बजट एक फरवरी को ही पेश होगा।

में शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बजट एक फरवरी को ही (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘क्या 100 दिन काम देने की गारंटी के स्थान पर 125 दिन काम देने की गारंटी गलत है’

भाजपा ने जी राम जी विधेयक का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों पर ग्रामीण जनता व श्रमिक के हित के बहाने केवल राजनीति करने का आरोप लगाया

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 दिसंबर। भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिये गये हैं। सबसे पहले लोकसभा को, तथा इसके बाद राज्यसभा को स्थगित किया गया।

राज्यसभा की बैठक गत आधी रात के बाद तक चली और वीबी-जी राम-जी विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया, जिसे इससे पहले, दिन में लोकसभा द्वारा मंजूरी दी जा चुकी थी। शुक्रवार को कार्यवाही दोबारा शुरू होने के कुछ ही समय बाद लोकसभा

को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। निचले सदन में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चर्चा हुये बिना ही शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। वीबी-जी राम-जी विधेयक पर बहस के बाद केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने महात्मा गांधी के आदर्शों की इससे पहले भी कई बार हत्या की है।

चौहान ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान मनरेगा भ्रष्टाचार से ग्रस्त था और निर्धारित कार्यों के लिए सामग्री की खरीद पर अपेक्षित धनराशि खर्च नहीं की गई।

एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रधानमंत्री और विपक्षी सदस्यों के बीच हुई बैठक की जानकारी दी। चर्चा में निर्वाचन क्षेत्र

- “क्या अधिक दिन काम देने का वादा, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों के खिलाफ हो सकता है।”
- भाजपा नेताओं ने, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, जी राम जी विधेयक के पारित होने पर 12 घंटे के लिए धरने पर बैठें सांसदों को लक्ष्य बनाया और कहा, उनकी “गुंडागर्दी” के कारण सदन नहीं चल पाया और दिल्ली में प्रदूषण पर होने वाली सारगर्भित बहस को भी टालना पड़ा।

से जुड़े मुद्दे और नए संसद भवन में एक अलग हॉल की मांग शामिल थी। एक वरिष्ठ मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुराने संसद भवन में ऐसी ही एक सुविधा थी, जिसका उपयोग यदा-कदा ही होता था।

कामयाब” गीत गा रहे हैं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा महात्मा गांधी की एक बार फिर हत्या की गई।

भगत ने कहा, “उत्पके (भाजपा) मातृ संगठन ने 1948 में गांधी जी की हत्या की थी और कल मोदी जी की सरकार ने गांधी जी के नाम की हत्या कर दी। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है कि उसे उन चीजों से चिढ़ (एलजी) है, जिनमें गांधी जी और नेहरू जी का नाम आता है। वे उन नामों को मिटा देना चाहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका नकारात्मक रही। इसलिए उन्होंने (भाजपा) ऐसा किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस (मनरेगा) पर बहुत

निर्भर थी... अगर सरकार चाहती तो खासियों को दूर कर, सुधार कर सकती थी... लेकिन वे तो गांधी जी का नाम हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।

केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वीबी-जी राम-जी विधेयक को लेकर तृणमूल कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन पर तोखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “जिनका मजदूरों से कोई लेना-देना नहीं है, केवल वही वीबी-जी राम-जी विधेयक 2025 का विरोध करेंगे। जो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, वही इसका विरोध करेंगे। क्या 100 दिन की जगह, 125 दिन की गारंटी देना गलत है? यह मजदूरों के हित में है। जो इसका विरोध कर रहे हैं, वे मजदूरों के दुश्मन हैं।”

भोमपुरा गांव की गौशाला में तीन माह में 1०० से ज्यादा गौवंश की मौत

दानदाता और रक्षक दलों का आरोप है कि 100 गायों की मौत हुई है, प्रशासन ने 70 की पुष्टि की

श्रीगंगानगर, (निर्स)। जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र के भोमपुरा गांव की गौशाला में 1०0 से ज्यादा गाय पिछले तीन महीने में मर चुकी हैं। अब भी 60 गायें तड़प रही हैं, जो जहां हैं वहीं पड़ी हैं, गर्दन तक नहीं उठा पा रही हैं। ठंड, दूषित भोजन और गीला चारा वजह बताई जा रही है।

गौशाला के पीछे पहुंचते ही प्रबंधन की लापरवाही नजर आई, यहां एक के ऊपर एक 7० गायों के शव पड़े मिले। पूछने पर पता चला इन्हें दफनाया जा रहा था। गौसेवकों ने जब मामले का खुलासा किया तो ये काम रोक दिया गया। यहीं कुछ दूर गायों के दफन शव जमीन से झांकते हुए नजर आए। अध्यक्ष बीमारी और घर में बेटे की शादी का बहाना बना कर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दानदाता और जो रक्षक दलों का आरोप है कि यहां 1०० गायों की मौत हुई है। जबकि प्रशासन ने 7० की पुष्टि की है। मामला भोमपुरा गांव की इच्छापूर्ण गोकुल गौशाला का है।

मुक्तिधाम मुकाम (नोखा) के कथावाचक और दानदाता राजन प्रकाश (36) ने इस मामले में समेजा कोठी पुलिस थाने में आरोपी गौशाला अध्यक्ष पालाराम बिशोई, मैनेजर सुनील व

- मामले में समेजा कोठी पुलिस थाने में गौशाला अध्यक्ष, मैनेजर व गौशाला कमेटी के अन्य सदस्यों के खिलाफ गौ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कराया**

गौशाला कमेटी के अन्य सदस्यों के खिलाफ गौ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कराया है। दानदाता राजन प्रकाश ने कहा कि गौशाला को साल में 2 बार अनुदान मिलता है। इस बार भी अनुदान मिला है। मैं खुद इस गौशाला से काफी समय से जुड़ा हूं और 1० महीने पहले मैं यहां व्यक्तिगत 1० लाख रुपए दान दिया था। इसके अलावा मेरे भक्तों ने भी ढाई लाख रुपए गौशाला में डोनेट किए थे। अगर इसमें से आधा पैसा भी गौशाला में लगता तो गौशाला की ऐसी स्थिति नहीं होती और गोवंश की मौत नहीं होती। गौशाला का पूरा पैसा व्यक्तिगत खर्च किया गया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

गौ रक्षा दल, रायसिंहनगर के अध्यक्ष बबलू भाटी ने बताया कि एकद्वार महीने में हमने गौशाला की वित्तायत की थी। इस दौरान पशुपालन विभाग ने यहां दौरा किया था और अव्यवस्थाएं देख प्रबंधन को 15 दिनों में सुधार के निर्देश दिए गए थे। इसके

बाद भी प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद सूचना मिली कि बड़ी संख्या में यहां मृत गायों को दफनाया जा रहा है। तब गोरक्षा दल की टीम यहां तहसीलदार हर्षिता और एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे। गायों को दफनाने और गौशाला की हालत देख चौंक गए।

बबलू भाटी ने बताया कि यहां 6० गाय मरने की हालत में थी, 1०० को दफनाने की तैयारी थी। सर्दी के मौसम में न तो गायों के लिए सूखे चारे की व्यवस्था थी न ही साफ-सफाई। इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल था।

मामले को लेकर कलैक्टर डॉ. मंजू चौधरी ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार, एसडीएम सुभाष चौधरी और पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक शामिल हैं। माहौल शांत रखने के लिए गौशाला में पुलिस

तैनात कर दी गई। नए प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत प्रशासक रिछपाल बावरी को सौंपी गई है।

कलैक्टर ने बताया कि इसके अध्यक्ष पालाराम बिशोई ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रथम दृष्टया ठंड और दूषित चारे से गायों की मौत होना सामने आया है। कलैक्टर ने कहा कि हमने गौशाला का निरीक्षण किया है। जिसमें गौशाला प्रबंधन समिति और उसके अध्यक्ष की घोर लापरवाही सामने आई है। जिसके कारण 6० से अधिक गोवंश की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कुछ गोवंश बीमार भी हैं, हमने एडीएम अनुपगढ़ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टरों की टीम भी यहां पर मौजूद है। गोवंश का पोस्टमॉर्टम कराया गया है और सैपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

कलैक्टर ने बताया कि राज्य सरकार से इस गौशाला को इस वित्तीय वर्ष में 64 लाख का अनुदान भी मिला है। 2 किस्तों में अनुदान दिया गया है। इस मामले में सरकार की ओर कोई कोताही नहीं है। इस मामले में कमेटी जांच करेगी और जो भी कोई अधिकारी या कर्मचारी भी दोषी पाया

जयपुर निवासी छात्र की नहर में गिरने से मौत

कोटा, (निर्स)। कुन्हाड़ी थाना इलाके में गुरूवार शाम को नहर में डूबे छात्र का शव शुक्रवार को नान्ता क्षेत्र में मिला। छात्र की तलाश में जुटी निगम गोताखोर टीम व एसडीआरएफ टीम ने नान्ता इलाके से नहर में शव को बरामद कर नान्ता पुलिस को सौंपा।

गुरूवार शाम को छात्र दोस्तों के साथ घूमने निकला था और कुन्हाड़ी इलाके में नहर में हाथ धोने के लिये उतरा था, लेकिन पैर फिसलने से छात्र नहर में बह गया। सूचना पर कुन्हाड़ी पुलिस व नगर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची। सूचना पर एसडीआरएफ भी पहुंची और छात्र की तलाश के लिये रेस्क्यू अभियान चलाया। कुन्हाड़ी थानाधिकारी मोंगेलाल यादव ने बताया कि नहर में डूबे छात्र की तलाशी के लिये गोताखोर और एसडीआरएफ टीम द्वारा अभियान

- कोटा में रहकर सेफ्ट स्टडी कर नीट की तैयारी कर रहा था छात्र**

चलाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि रात्रि को अभियान बंद कर शुक्रवार सुबह से छात्र की तलाश के लिये रेस्क्यू अभियान चलाया गया और नान्ता क्षेत्र में छात्र का शव बरामद हुआ। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक छात्र जयपुर निवासी लोकेश कुमावत था, सूचना पर परिजन भी कोटा पहुंच गये थे। छात्र कोटा में रहकर सेल्फ स्टडी कर नीट की तैयारी कर रहा था। नान्ता थानाधिकारी चेतन कुमार ने बताया कि नहर में डूबे छात्र का शव बरामद हुआ। मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

डीडवाना : अज्ञात कारणों से दर्जनों गौवंश की मौत

- गौशाला प्रबंधन की ओर से खेत में ही गड्ढा खोदकर गायों को दफन किया जा रहा है**

तक अज्ञात है। गायों में मौत की वजह कोई अज्ञात बीमारी है या भूख की वजह से गाये मर रही हैं। आरोप है कि गौशाला प्रबंधन द्वारा ही मौतों की सूचना समय पर पशुपालन विभाग को नहीं दी गई और मृत गौवंश को जेसीबी से गड्ढे खुदवाकर खेतों में चुपचाप दफनाया गया।

स्थानीय लोगों का दावा है कि अब तक सैकड़ों गौवंश को गुपचुप तरीके से दफनाया जा चुका है, सितंबर माह में भी अज्ञात कारणों से सैकड़ों गौवंश की मौत हुई थी। गौहकरी की मौत फिन कारणों से हुई, यह फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है।

मुख्यमंत्री आज मांडलगढ़ का दौरा करेंगे

भीलवाड़ा, (निर्स)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2० दिसंबर को भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजकीय उच्च

- ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन करेंगे सीएम**

माध्यमिक विद्यालय, माँडलगढ़ में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा हेलीकॉप्टर द्वारा मांडलगढ़ पहुंचेंगे और ग्रामीण समस्या समाधान शिविर में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा के इस दौरै से जिले के लोगों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री के दौरै के दौरान जिले के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरै के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जिले के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे।

दो पक्षों में हुए झगड़े में एक नाबालिग की हत्या

डींग/भरतपुर, (निर्स)।जुरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम अहलवाड़ी में शुक्रवार को दो पक्षों में हुए झगड़े में एक नाबालिग लड़के की जान चली गई। गांव के दो पक्षों में बिजली की टंकी को लेकर शुरू हुए विवाद ने इतना बड़ा रुप ले लिया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के नाबालिग लड़के के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। मृतक के शव का जुरहरा के राजकीय किरोड़ीलाल स्वर्णकार अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतक के पिता ने नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। घटना की सूचना पर एएसपी कामां व सीओ कामां ने ग्राम अहलवाड़ी का दौरा कर घटना के संंध में जानकारी लेकर जुरहरा थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अहलवाड़ी को दो दिन पहले गुम हुए चार साल के बच्चे की हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ है और शुक्रवार को फिर से गांव में एक और नाबालिग

की हत्या ने सभी को चौंका दिया है। जुरहरा कस्बा सहित ग्रामीणांचल में ग्राम अहलवाड़ी में हुए दोनों हत्याकांडों की चर्चा आम हो गई है। शुक्रवार को कुल्हाड़ी के वार से हुई हत्या के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के पिता शकिर पुत्र रमजानी मेव निवासी ग्राम अहलवाड़ी ने जुरहरा थाने में मामला दर्ज कराकर बताया कि वह व उसका भतीजा आदिल बिजली कनेक्शन की फाईल लगाकर बिजली कनेक्शन लेने व बिजली टंकी को सही कराने के बारे में बात कर रहे थे तभी गांव के ही अख्जर पुत्र कालू ने वहां आकर बेवजह उनके साथ गाली-गलौच करनी शुरू कर दी। इसके कुछ देर बाद ही अख्जर व उसके परिजन लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी एवं सरिया लेकर उनके घर आ गए। जिन्होंने घर के बाहर बैठे उसके 16 वर्षीय नाबालिग पुत्र दानिश पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसके सिर में गम्भीर चोट आ गई। इस दौरान आरोपी पक्ष ने पथराव भी किया जिससे उसके और भी परिजनों

को चोटें आई हैं। शिकायत में बताया गया है कि गम्भीर हालत के कारण दानिश को जुरहरा चिकित्सालय से भरतपुर रेफर किया गया, लेकिन भरतपुर ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

जुरहरा थानाधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस जात्ता तैनात किया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जायेगी।

अहलवाड़ी हत्याकांड में मृतक के पिता के द्वारा पुलिस में दर्ज कराये गये मामले में अख्जर पुत्र कालू, इसलाम पुत्र कालू, जाबिदा पत्नी अख्जर, फरमान पुत्र मुस्तुफ, अरसीदा पत्नि मुसद्दी, सकूनत पुत्री इस्लाम, असलम पुत्र भूक, सुबीन पुत्र हमीदा, धौली पत्नी शकुल, साहिदा पत्नी बुबेर, सहवाना पुत्री अख्जर, आईफा पुत्री मुसद्दी व बरफीना पत्नी मुबारिक को आरोपी बनाया गया है।

अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियाई नागरिक को डिटेन्शन सेंटर भेजा

अजमेर, (निर्स)। राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अवैध रूप से निवास करने एवं ओवरस्टे कर रहे विदेशी नागरिकों के विरुद्ध चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत सीआईडी (विशेष शाखा) अजमेर द्वारा एक नाइजीरियाई नागरिक के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत संबंधित विदेशी नागरिक को डिटेन्शन सेंटर, अलवर भेजा गया।

सीआईडी (विशेष शाखा) अजमेर के एएसपी राजेश मीना ने बताया कि नाइजीरियाई नागरिक अब्दुल बासित अयूबा मुहम्मद ने वर्ष 2०23 में भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर में बीएससी आईटी पाट्यक्रम में प्रवेश लिया था। जांच में सामने आया कि वह नियमित रूप से विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं रहा, न ही परीक्षाओं में शामिल हुआ। इसके बावजूद बीजा की वैधता समाप्त होने के बाद भी वह लगातार ओवरस्टे करता रहा, जो बीजा नियमों का स्पष्ट

उल्लंघन है। विदेशी छात्र की अनियमित गतिविधियों एवं बीजा नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सीआईडी द्वारा प्रकरण की जांच की गई। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संबंधित नाइजीरियाई नागरिक को उसके देश डिपोर्ट किए जाने तक डिटेन्शन सेंटर में निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए गए। इन आदेशों की पालना में शुक्रवार को पुलिस गार्ड के साथ उक्त नाइजीरियाई नागरिक को डिटेन्शन सेंटर, अलवर भेजा गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया

ट्रक यूनियन की जमीन पर जेसीबी से अवैध प्लॉटिंग तोड़ी

अलवर, (निर्स)। अलवर यूआईटी ने एक बार फिर शुक्रवार को दिवाकारी के निकट साकेत नगर योजना से लागती ट्रक यूनियन की करीब 25 से 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग तोड़

- साकेत नगर योजना से लागती ट्रक यूनियन की करीब 25 से 30 बीघा जमीन पर कार्रवाई की**

दी। 4-4 जेसीबी ले जाकर दीवारों को ढहाया गया। ग्रेवल रोड भी उखाड़ी। पहले भी इसी जगह पर अवैध प्लॉटिंग को यूआईटी ध्वस्त कर चुकी है।

अलवर यूआईटी के अतिरक्मण निरोधक अधिकारी मानवेंद्र जायसवाल ने बताया कि अलवर में दिवाकारी के निकट चंद्रमोली मोटर्स के पीछे बड़ी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। मौके पर करीब 25 से 3०



अलवर यूआईटी ने ट्रक यूनियन की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी तोड़ दिया।

बीघा जमीन पर ग्रेवल रोड डाल दी थी। इसके अलावा काफी प्लॉट की बाउंड्री हो चुकी थी।

इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यहां पहले भी यूआईटी के दस्ते ने

तीन भाइयों व भतीजे की मौत की खबर से मातम पसरा

टोंक, (निर्स)। शहर में सभी की आंखें उस समय नम हो गईं, जब तीन भाइयों और उनके भतीजे की मौत की खबर मिली, सूचना के बाद मृतकों के घरों में चीख-पुकार मच गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यालय के बड़ा कुआं क्षेत्र में राज टंकीज रोड स्थित विवेकानंद स्कूल के पीछे रहने वाले एक ही परिवार के पांच लोग गुरुवार शाम क्रेटा कार से कोटा अपने रिश्तेदार के पोते के जन्मदिन की पार्टी में जा रहे थे। घटना बूंदी स्थित जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे 52 के सिलीर पुलिया पर गुरुवार की शाम को हुई, हादसे के दौरान कार पर बजरी से भरा डंपर पलट गया।

इससे एक भाई ने तो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली जबकि तीन भाई और उनके एक भतीजे की डंपर के नीचे दबने से कार में ही मौत

हो गई। बाद में देर रात्रि को तीनों भाई और भतीजे का शव घर आया तो चीख-पुकार मच गई। मृतकों में फरीउद्दीन, अजीरूद्दीन, मोइनुद्दीन तीन भाई व भतीजा सेफुद्दीन थे। इनमें सेफुद्दीन का पिता वसीउद्दीन सड़क हादसे में कार की खिड़की खुलने से बच गया। शुक्रवार की सुबह पूरे मोहल्लेवासी मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों को संभाला तथा इसके बाद जनाजा निकाला गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा तेज रफ्तार से आ रहे डंपर का आगे का टायर अचानक फटने डंपर असंतुलित होकर कार पर पलट गया, जिससे एक व्यक्ति को छोड़कर चारों

लोग डंपर पर और बजरी के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में मौके पर मौजूद राहगीरों व थाना पुलिस द्वारा सभी को बाहर निकाला जा सका।

तीन बूथ लेवल अधिकारी निलम्बित

टोंक, (निर्स)। विधानसभा क्षेत्र टोंक (१6) में कार्य में लापरवाही बरतने, कर्तव्य पर उपस्थित नही होने व आदेशों की अवहेलना करने के कारण तीन बूथ लेवल अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपखण्ड अधिकारी टोंक हुक्मीचन्द रोहलानिया ने निलम्बित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी टोंक ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र टोंक में नव सृजित मतदान केन्द्रो पर नियुक्त किये गये 3 बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने पर राजकीय दरबार उमावि टोंक के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सोरभ जैन, राउमावि मालियों की झोपड़िया मेहन्दवास के कनिष्ठ सहायक लोकेश झारोटिया व राउप्रावि शुक्लपुरा हथोना प्रबोधक इसरार अहमद को निलम्बित किया गया है। निलम्बन उपरान्त तीनों कार्मिकों का मुख्यालय तहसील कार्यालय टोंक रखा गया है।

थाईलैंड से पार्सल में आया अवैध नशीला पदार्थ जब्त

कोटा, (निर्स)। मादक पदार्थ विरोधी अभियान को जारी रखते हुए मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) जयपुर सेल के अधिकारियों ने एफपीओ कस्टम्स जयपुर में थाईलैंड से आए एक इंटरनेशनल पार्सल की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान टीम को पार्सल में ०.650 किलोग्राम अवैध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।

उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि थाईलैंड से एफपीओ कस्टम्स में आए एक पार्सल में खाने की चीजों के साथ छिपाकर अवैध हाइड्रोपोनिक वीड होने का शक है। उक्त सूचना पर केन्द्रीय

- जब्त हाइड्रोपोनिक वीड की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई**

नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) जयपुर सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और उस पार्सल की तलाशी के लिए एफपीओ जयपुर भेजा गया।

उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि तलाशी के दौरान टीम को हाइड्रोपोनिक वीड की तीन अलग-अलग पैकेट मिले, जिनका नाम सुपरबुफ (कैलिफोर्निया, यूएस का ओरिजिन) जिसका वजन ०.32० किलोग्राम, द किलर क्वीन (ब्रिटिश

कोलंबिया का ओरिजइन) जिसका वजन ०.11० किलोग्राम और द आइसक्रीम केक (वेस्ट कोस्ट, यूएस का ओरिजिन) जिसका वजन ०.220 किलोग्राम था, यानी कुल ०.650 किलोग्राम अवैध हाइड्रोपोनिक वीड पार्सल चिप्स के पैकेट के नीचे छिपा हुआ बरामद किया गया।

उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि जब्त किए गए हाइड्रोपोनिक वीड की अवैध बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद बरामद हाइड्रोपोनिक वीड को एनडीपीएस अधिनियम का तहत जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

अलवर जिला परिषद की ओर से की गई लिपिक भर्ती में बड़ा खुलासा

अलवर, (निर्स)। अलवर जिला परिषद की ओर से करीब तीन साल पहले की गई 134 लिपिकों की भर्ती में एक और चौकाने वाला मामला सामने आया है। दो केस ऐसे सामने आए हैं, जिन्होंने लिपिक बनने के लिए आवेदन तो किया, लेकिन उनका नाम न प्रतीक्षा सूची में था और न ही उन्होंने अपने दस्तावेज जमा कराए। नौकरी मिलने के तीन साल बाद अब इस मामले का खुलासा हुआ है, जो जांच अधिकारी एडीएम सिटी बीना महावर के पास पहुंचा है। बताते हैं कि उन्होंने दस्तावेज तलब किए हैं।

लिपिक भर्ती के तहत प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए कुल 286 लोगों की तरफ से आपत्ति दायर की गई थी। आपत्ति निराकरण सूची में शामिल 189 और 224 नंबर पर दर्ज आपत्ति को आपत्ति निराकरण समिति ने इनके प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने की आपत्ति

- न वेंटिंग लिस्ट में नाम, न दस्तावेज जमा कराए, फिर भी बन गए लिपिक**

को यह कहकर खारिज कर दिया कि इनके प्रार्थकों तीन गुना कट ऑफ में नहीं आते। इसी वजह से इन दोनों अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया और न ही दस्तावेज सत्यापन का मौका दिया गया। इसके बाद जिला परिषद की ओर से 24 नवंबर 2०22 को जारी आदेश में एक महिला अभ्यर्थी को मालाखेड़ा और 3० दिसंबर को जारी आदेश में पुरुष अभ्यर्थी को रामगढ़ पंचायत समिति में लिपिक पद पर नियुक्ति दे दी गई।

एडीएम सिटी को जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) आरती गुप्ता की ओर से

करीब दो माह पहले भेजी गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इन दोनों ने प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए आपत्ति दी थी, लेकिन अपात्र होने के कारण इनका नाम दस्तावेज सत्यापन की सूची में नहीं था और इन्होंने अपने दस्तावेज इस कार्यालय में जमा भी नहीं कराए। सबसे खास बात यह है कि जिस आवेदन क्रमांक पर महिला अभ्यर्थी की आपत्ति खारिज की गई, उस आवेदन क्रमांक के स्थान पर दूसरे आवेदन क्रमांक को बदलकर महिला को नौकरी दे दी गई। दोनों आवेदन पर आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और प्रार्थनांक समान हैं। जांच अधिकारी एडीएम सिटी बीना महावर की ओर से इनके दस्तावेज तलब किए गए हैं। ऐसे ही करीब 15 और अभ्यर्थी हैं, जिनके दस्तावेज एडीएम सिटी ने मंगवाए हैं। इनको ज्यादा नंबर होने के बावजूद नौकरी नहीं दी गई।

मवेशी काटने का वीडियो वायरल, पोटला ग्राम में बवाल

हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने दुकानें बंद करा दी और सड़कों पर प्रदर्शन किया

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के पोटला गांव में बागरिया समुदाय के लोगों द्वारा मवेशी काटने का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से तनाव चरम पर पहुंच गया। हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने बाजार और दुकानें बंद करा दी और सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी परिवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई है।

घटना की शुरुआत पोटला निवासी गोवर्धन बागरिया के घर पर एक शादी समारोह से हुई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि घरलू कार्यक्रम के दौरान भैंस (मवेशी) काटा गया था। गोवर्धन के भांजे रतनलाल बागरिया ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें मवेशी की गरदन लहराते हुए दिखाया गया। वीडियो वायरल होते ही गांव में



आक्रोशित लोगों ने पोटला ग्राम के बाजार बंद करवा दिये।

आक्रोश फैल गया। पोटला में बागरिया समुदाय के मात्र 15 से 25 परिवार निवास करते हैं, लेकिन इस वीडियो ने पूरे इलाके का माहौल गरमा दिया। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने सुबह से

ही सड़कों पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी।

बाजार पूरी तरह ठप हो गया, जबकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गंगापुर एसडीएम, पुलिस

उपाधीक्षक सहित जान्ना मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी हुई है।

सार-समाचार

हजारों लीटर वॉश व भड़ियां नष्ट

उदयपुर, (कासं)। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत नकाबंदी, गश्त, रेड की प्रभावी कार्यवाही कर अभियोग दर्ज किए गए। आबकारी आयुक्त श्री नकाते के निर्देशानुसार अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओपी जैन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत के सुपरविजन में प्रदेश में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।उज्जयपुर में जमवारामगढ कांकरेल वन क्षेत्र में आबकारी निरोधक दल की कार्रवाई में वॉश एवं भड़ियां नष्ट की गईं। डूंगरपुर जिला सागवाड़ा क्षेत्र के रोंदा, फला ओबरी व कडाना बेक वाटर के मेटीटंबा में 6 हजार लीटर वॉश एवं 1३ भट्टी नष्ट की गई साथ ही ३५ लीटर अवैध मह्दुआ शराब जब्त की गई। बीकानेर के श्रीकरणपुर में दबिश की कार्रवाई में ६०० लीटर वॉश नष्ट किया एवं १२ लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त की गई। मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर २ अभियोग दर्ज किया। हनुमानगढ में टिब्बो, सुरेवाला क्षेत्र में २०० लीटर वॉश नष्ट कर १५ लीटर अवैध शराब जब्त की गई। अलवर जिले में पडत मदिरा क्षेत्र डिगावडा, राजगढ व सूटी में कार्रवाई के तहत ४० पेटी विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब जब्त की गई और एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में आबकारी क्षेत्र सदरपुरा एवं जोधपुर पश्चिम की नट बस्ती, मसूरिया व तनावडा में कार्रवाई के तहत ४५० लीटर वॉश नष्ट करते हुए ३ अभियोग दर्ज किए। बांसवाडा में आबकारी निरोधक दल ने दबिश देकर २२०० लीटर वॉश नष्ट कर ४ अभियोग दर्ज किए। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी निरोधात्मक अभियान के तहत नकाबंदी, दबिश व सप्नन गश्त की जा रही है।

हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल थाना पुलिस ने कार से टक्कर मार कर व्यक्ति की हत्या करने के बाद हादसे को घटना बताने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार १९ दिसंबर को पीडित भंवरलाल गारु निवासी मल्लातलाई ने एक अज्ञात वाहन द्वारा स्वयं के दोहिले आरव खोखर व उसके साथी हिमांशु के सूट्री से किशनपोल से मल्लातलाई आते समय मोरारावाड़ी में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से चोटिल आरव की मृत्यु हो गई एवं हिमांशु गंभीर घायल हो गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर किए गए अनुसंधान एवं मामले में घायल हिमांशु द्वारा हत्या करने की जानकारी दी। इस मामले में सामने आया कि कार नं सवार तीन बदमाश सोहेल उर्फ टोनी पुत्र मुनिरा खां निवासी ओमबक्वा दक्षिणी विस्तार कॉलोनी , मोहसनी पुत्र मोहसनी निवासी नूरी चौक खांजीपीर व सोहेल पुत्र शेर मो. निवासी अंजुनम हॉल गोसिया कॉलोनी उदयपुर ने १८ सितंबर रात में बलीचा क्षेत्र से सिगरेट की की बात को लेकर हिमांशु कुलराण व आरव खोखर से हुई कहासूनी होने पर कार लेकर स्कूटी के पीछे रवाना हुए। जहां बीच रास्ते में टक्कर मारने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी दौरान मोगरा वाड़ी क्षेत्र में मौका पाते ही स्कूटी को टक्कर मार आरव की हत्या कर दी तथा हिमांशु को गंभीर घायल कर फरार हो गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उपाधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सुपरविजन में सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह चौहान के नेतृत्व में गठित दल ने कार्यवाही करते हुए अनुसंधान में एसआई विमलसिंह, एसआई शरीफ खान, चन्द्रभानसिंह, सीओ कार्यालय हेडकांस्टेबल इन्द्रजीतसिंह मय टीम ने तलाश शुरु की। इस दौरान रेल्वे स्टेशन के पास पुलिस को देख कार साईड में खड़ी कर दिवार फांद कर भागने लगे। जिसके चलते तीनों के पांच चोटिल हो गए। इस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से वाइरदा में प्रयुक्त कार बरामद की। आरोपी सोहेल उर्फ टोनी गोवर्धन विलास पुलिस थाने का हिस्ट्रीशिटर होकर उसके खिलाफ शहर के अनलग अलग थानो में छह से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक सूर्यवीरसिंह राठोड़ कर रहे है।

चयनित अर्थर्थियों की सूची जारी

उदयपुर, (कासं)। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यार्थियों को शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक माप तौल परीक्षा ८, ९ एवं १० दिसम्बर को गांधी टाउंड में आयोजित गठित बोर्ड के समक्ष हुई। जिसमें कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी ३८५ व कांस्टेबल चालक नॉन टीएसपी के १७ तथा सामान्य टीएसपी के ८८ अभ्यर्थियों का चयन कर सूची तैयार की गई। चयन बोर्ड द्वारा तैयारी सूची को राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड की गई है तथा चयनित अभ्यर्थियों की सूचनी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय उदयपुर एवं रिजर्व पुलिस लाइन उदयपुर नोर्टिस बोर्ड पर चप्स्य की गई है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन, बायोमैट्रिक सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण २३ से २७ दिसंबर तक रिजर्व पुलिस लाइन उदयपुर में होंगे। गोयल ने चयनित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित अन्य दस्तावेज और १० पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लेकर निर्धारित दिनांक को रिजर्व पुलिस लाइन में प्रातः१० बजे उपस्थित हों। चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा रिजर्व पुलिस लाइन में नोर्टिस बोर्ड पर भी चप्स्य कर दी गई है। भर्ती में कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी ३८५, कांस्टेबल चालक नॉन टीएसपी १७ तथा कांस्टेबल सामान्य टीएसपी के ८८ अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए जब्त

उदयपुर, (कासं)। डीएसटी एवं भुपालपुरा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा,पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सुपरविजन में भुपालपुरा थानाधिकारी कानामराम एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए शास्त्री सकल के पास से आरोपी दानिश उर्फ डिफे पुत्र ईब्तुल्ला निवासी जूडीधरों का मोहल्ला पृथुखी चौक धानमण्डल के कब्जे से ५.९७ तना अवैध मादक पदार्थ एमडीएमएजब्त कर गिरफ्तार किया। इसी दौरान कार्यवाही करते हुए आयड महासतीया के बाहर से आरोपी मो. साहिल पुत्र मो. शराफत निवासी लौहरा कॉलोनी आयड के कब्जे से १.७५ ग्राम अवैध एमडीएमए जब्त कर गिरफ्तार किया।

नई पुलिस चौकी का उद्घाटन

उदयपुर, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने शुक्रवार को फिनोवा केपिटल प्राईवेट लि. कंपनी के सहयोग से पत्राधाय मार्ग हाथीपोल पर अस्थाई पुलिस चौकी व अम्बेरी में यातायात बृ्ध एवं पुलिस सहायता केन्द्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश यादव एवं यातायात पुलिस उप अधीक्षक अशोक आंजना, हाथीपोल थानाधिकारी राजुदेवी एवं हाथीपोल व्यापार मण्डल के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

हादसे में वृद्ध की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में हुए हादसे में घायल वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रकरण के अनुसार १५ दिसंबर को अज्ञात वाहन को चपेट में आने से घायल मनोहरगुप्त बढागांव निवासी सगुनोथ (६८) पुत्र भूरानाथ कालबेलिया को हमपी चिकित्सालय में अज्ञात व्यक्ति ने भर्ती करवाया। जिसकी उपचार के दौरान मौत होने से शिनाख्त नहीं हो पाई थी। शुक्रवार को इसका पता चलने पर पुत्र गोविन्दनाथ ने मोर्चा में पहुंच कर मृतक की अपने पिता पारुन्नाय के रूप में शिनाख्त की। इस पर हेडकांस्टेबल नितेश मेनारिया ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिवजनों को सौंप दिया।

पिम्स हॉस्पिटल में रोगी का सफल उपचार

उदयपुर, (निस्)। पैसिफिक इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उमरडा के रेस्पिरेट्री मेडिसिन विभाग में ६६ वर्षीय पुरुष रोगी का सफलतापूर्वक उपचार किया गया है।चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने बताया कि संस्थान में रोगी पिछले दो माह से श्वसन सम्बन्धी समस्या के चलते अस्पताल आया। जाँच के दौरान छाती के पेक्स-रे एवं एचआरसीटी स्कैन में बार्र फेफड़े में अत्यधिक (ग्रॉस) प्फ्यूरल इम्फ्यूजन पाया गया, जिसके कारण बार्रै फेफड़े का पूर्ण संकुचन हो गया था। चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने बताया कि रोगी की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक ओपन थोरेसिक सर्जरी के स्थान पर न्यूनतम इन्वेसिव थोरेकोस्कोपी प्रक्रिया अपनाई गई। इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से लंबे समय तक अस्पताल एवं आईसीयू में भर्ती रहने, अधिक खर्च तथा संभावित जटिलताओं से बचाव संभव हुआ।

जिला कारागृह व उपकारागृह सागवाड़ा का किया निरीक्षण

डूंगरपुर, (निस्)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश की सचिव मनोज मीना ने शुक्रवार को जिला कारागृह डूंगरपुर एवं उपकारागृह सागवाडा का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष सुनील कुमार पंचोली ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शंशि उर्फ शाही चिकना विवेकानन्द जुरमानी बनाम महाराष्ट्र राज्य प्रकरण में परित हालिया निर्णय का संदर्भ दिया। उन्होंने बताया कि

सर्वोच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपी को बार.बार पेश न किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि ट्रायल के दौरान आरोपी की प्रत्यक्ष उपस्थिति एक निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। यह प्रक्रिया मानवाधिकारों के दुरुपयोग को रोकने और बंदियों को सीधे न्यायाधीश के सामने अपनी शिकायतें रखने में सक्षम बनाती है तथा आरोपी को समय पर पेश न करना एक मौलिक सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।।

अध्यक्ष ने जेल प्रशासन को स्पष्ट किया कि इस विशेष निरीक्षण और

अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्यवाई करना है,से विचाराधीन बंदियों को चिन्हित करना जिन्हें अदालतों में पेश होने में समस्या आ रही है और पेश न हो पाने के कारणों का दस्तावेजीकरण करना,पुलिस जाब्ता या अन्य संसाधनों की कमी के कारण पेशी प्रभावित होने वाली तकनीकी समस्याओं को रिकॉर्ड करना,ऐसे विचाराधीन बंदी जिन्होंने कानून के तहत निर्दिष्ट अधिकतम सजा का आधा या एक-तिहाई हिस्सा हिरासत में बिता लिया है उनकी पहचान कर राहत प्रदान करना तथा ऐसे बंदियों की सूची तैयार करना जिनका कोई वकील नहीं है या जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने निर्देश

दिए कि जिन बंदियों को कानूनी सहायता

की आवश्यकता है, उनके लिए तत्काल

जमानत आवेदन दाखिल किए जाएं,पेशी

से संबंधित आवश्यक प्रार्थना पत्र

न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं नि:शुल्क

विधिक सहायता योजना के तहत अनुभवी

वकील उपलब्ध कराए जाएं। अध्यक्ष

सुनील कुमार पंचोली ने कहा, न्याय

केवल कागजों पर नहीं,बल्कि धरातल पर

दिखना चाहिए। प्रत्येक बंदी को अपनी

बात अदालत के समक्ष रखने का

संवैधानिक अधिकार है और विधिक सेवा

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए

प्रतिबद्ध है कि कोई भी बंदी केवल

संसाधनों या जानकारी के अभाव में न्याय

से वंचित न रहे।

करंट की चपेट से हेलपर की मौत

डूंगरपुर, (निस्)। जिले के रामसागडा थाना क्षेत्र के नारेली गांव में एक बुलडोजर हेलपर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बुलडोजर का बकेट बिजली की लाइन से छू जाने के कारण

यह हादसा हुआ। घटना के बाद मृतक

के परिवजन मौताणे क्षतिपूर्ति की मांग को

लेकर घरेने पर बैठ गए।

महुडी निवासी अल्पेश रोत पुत्र

रमेश रोत बुलडोजर पर हेलपर का काम

करता था। गुरुवार को वह बुलडोजर

लेकर नारेली गांव में खुदाई के काम पर

गया था। इसी दौरान बुलडोजर का बकेट

बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया।

बिजली का झटका लगने से हेलपर

अल्पेश गंभीर रूप से झूलस गया और

बेहोश हो गया। उसे तुरंत डूंगरपुर

अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों

ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर

दिया। घटना को सूचना मिलने पर

रामसागडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची

और शव को अस्पताल की मोर्चरी में

रखवाया। मृतक के परिजन बुलडोजर

मालिक से मौताणे की मांग पर अड गए।

पुलिस ने परिवजनों को समझाने का

प्रयास किया। देर शाम को दोनों पक्षों के

बीच समझौता हो गया।

नियम तोड़ने वालों पर हो हो कठोर कार्रवाई: जिला कलेक्टर मेहता

व्यक्तियों के समस्त दस्तावेजों की सूक्ष्मता से पड़ताल की जाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों की कटाई एक अत्यंत संवेदनशील एवं पर्यावरण से जुड़ा विषय है। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर न केवल संबंधित व्यक्तियों बल्कि सरकारी तंत्र में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रभावित गांवों एवं क्षेत्रों का शीघ्र सर्वे कर विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर मेहता ने विभिन्न पहाड़ियों पर निर्मित सड़कों एवं अन्य संरचनाओं की स्वीकृतियों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन हुआ है, वहां किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना वैधानिक अनुमति किए गए प्रत्येक कार्य की गहन जांच की जाए तथा संबंधित

पाए जाएं, वहां नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि सभी कार्रवाईयां ग्रे-एनवायरमेंट दृष्टिकोण अपनाते हुए की जाएं। अवैध निर्माण एवं पहाड़ियों की अवैध कटाई किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाने वालों को खतेदारी निरस्त करने के साथ-साथ सीजर से संबंधित राजस्व विभाग एवं उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसडीएम गिरवां अलुला के कृष्ण, यूडीए उपायुक्त सुरेंद्र बी. पाटीदार, यूडीए तहसीलदार अभिनव शर्मा, रणजीत सिंह बिंदू, गिरवां तहसीलदार श्याम सिंह चारण, बड़गांव तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, खनन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित

भीम, (निस्)। उपखंड क्षेत्र के पू अभिलेख निरीक्षक व्रत बरार के अंतर्गत ग्रामीण समस्या शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया।

इस अवसर पर शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी विकास शर्मा ने बताया कि पू अभिलेख निरीक्षक व्रत बरार की क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरार,हामेला की रेवर, टीकरवास, कुशलपुरा, कुकरखेडा, आदि ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीण सेवा शिविर में उपखंड अधिकारी विकास शर्मा, तहसीलदार मनोज कुमार गांग, विकास अधिकारी कृष्ण मुरारी छालिया, नायब तहसीलदार निजामुद्दीन काठित, आदि की मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कहा-अरावली बचाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निस्तारण किया।

जमीन हड़पने का मामला

उदयपुर, (कासं)। सविना थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीडित की जमीन को धोखे से अपने नाम कराने का प्रकरण दर्ज किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित तकाराम पुत्र हिरा गमेती निवासी पडावली

इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा।

वक्ताओं ने कहा. अरावली को

केवल सौ मीटर की सामान्य पहाड़ी

मानना पूरी तरह गलत और भ्रामक है।

अरावली एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है जो

पर्यावरण,जल संरक्षण और जैव

विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अरावली

के अस्तित्व के साथ इस तरह की छेड़छाड़

जारी रही तो इसका गंभीर खमियाजा आने

वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। समिति

ने सरकार से अरावली पर्वतमाला को

लेकर स्पष्ट और ठोस नीति बनाने की मांग

की। प्रदर्शन में मेवाड़ महामंडलेवर रास

बिहारी शास्त्री, भाजपा के पूर्व शहर

जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित कई

सामाजिकए राजनीतिक और पर्यावरण

प्रेमी मौजूद रहे।

उधर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और

कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ की ओर से भी

प्रदर्शन हुआ। युवाओं और महिलाओं ने

सेव अरावली के माध्यम से झूलस गया और

लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले

के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने

कहा यदि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर

पुनर्विचार नहीं करता है तो उस आंदोलन

किया जाएगा। अरावली को केवल सौ

मीटर की पहाड़ी मानने को पर्यावरण और

मेवाड़ की अस्मिता के साथ अन्याय

बताया गया। प्रदर्शन में शहर जिलाध्यक्ष

फतह सिंह राठौड़,दिनेश श्रीमाली,वरिष्ठ

नेता धर्मेन्द्र राजोर, सत्यनारायण टांक,

ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह सहित कांग्रेस

कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे।

बैठक २२ को

उदयपुर, (कासं)। १२वें उदयपुर पक्षी मेले का आयोजन किए जाने हेतु पक्षी मेले से संबंधितपहुलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करने हेतु बैठक आयोजित की जाएगी। उप वन संरक्षक वन्यजीव यादवेन्द्र सिंह ने बताया कि बैठक का आयोजन मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में २२ दिसम्बर को होगी।

राजस्थान विद्यापीठ-ग्लोबल डेवलपमेंट कॉलेज ऑस्ट्रेलिया के बीच एमओयू

उदयपुर, (कासं)। उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से शुक्रवार को राजस्थान विद्यापीठ एवं और ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबल डेवलपमेंट कॉलेज के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। विद्यापीठ की ओर से कुलपति प्रो.एस. एस. सारंगदेवोत ग्लोबल डेवलपमेंट कॉलेज की ओर से कुलपति प्रो. जेरेमी नोवाक ने हस्ताक्षर किए।

उस समय का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग को

अकादमिक सदस्य एवं विद्यार्थियों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी नयी पहचान : प्रो. सारंगदेवोत

बढ़ावा देना, कौशल आधारित प्रशिक्षण के अवसर विकसित करना तथा शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इसके अंतर्गत विविधता व्याख्यान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उपरती तकनीकों से जुड़े शैक्षणिक प्रयास, तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए क्षमता

राजस्थान विद्यापीठ के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक संपर्क और अनुभव साझा करने का एक अवसर प्रदान करेगा, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को वैश्विक शैक्षणिक परिदृश्य को समझने

और उससे जुड़ने में सहायता मिलेगी। इस मौके पर कुलाधिपति कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर, पीठ स्थाविर डॉ. कौशल नागदा, प्रो. जगेंद्र माथुर, प्रो इंद्रजीत माथुर, डॉ सौरभ राठौड़ आदि मौजूद रहे।

सार-समाचार

45 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण

कपासन, (निस्)। कपासन नगर पालिका द्वारा कस्बे के श्री चारभुजा नाथ मंदिर और श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में कराए गए ४५ लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण आज शुक्रवार को किया गया। यह लोकार्पण विधायक अर्जुनलाल जीनगर और नगर पालिका अध्यक्ष मंजुदेवी सोनी ने किया। वार्ड १५ स्थित श्री चारभुजा नाथ मंदिर में अमावस्या के अवसर पर विधायक जीनगर के सानिध्य में ध्वजा चढ़ाई गई। इसके बाद, विधायक जीनगर और नपा अध्यक्ष सोनी ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और मंदिर में स्वागत द्वार सहित ३.४ लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। पंडित राजू व्यास ने पूजा संपन्न करवाई। इस अवसर पर मंदिर मंडल के अध्यक्ष कन्हैयालाल सोमानी सहित सदस्य रामेश्वर लाल सोमानी, अनिल सोमानी, कमलेश सोमानी, देवदार सोमानी और प्रशांत विजयवर्गीय ने अतिथियों का स्वागत किया। विधायक जीनगर ने पुजारी सुरेश कुमार वैष्णव का अभिनंदन भी किया।इसके पश्चात, वार्ड १३ में स्थित स्वर्णकार समाज के लक्ष्मीनाथ मंदिर में ११ लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। विधायक जीनगर और नपा अध्यक्ष सोनी ने यहां भी लोकार्पण समारोह में भाग लिया। स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष नंद किशोर सोनी, छितर मल सोनी, प्रकाश सोनी, रतन सोनी और मनोज सोनी सहित अन्य सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान पार्षद रोशन सोनी, कुलदीप सोनी, लोकेश राव और राजीव सोनी का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राज विजयवर्गीय, जी.एस.एस. अध्यक्ष नंदकिशोर बेराला, पूर्व नपा अध्यक्ष जगेंद्र बाघमारा, युवा मोर्चा अध्यक्ष विकास ठोेरामा, पार्षद अशोक विजयवर्गीय, वंदना सोनी, वंदना दाधीच, पुष्पा वैष्णव, लता वैष्णव, रोशन सोनी, कुलदीप सोनी, राजीव सोनी, जिनेंद्र कोठारी, राजेश जाजू, तरुण बरेगामा, किसान मोर्चा अध्यक्ष शंभू बागडा, भागीरथ, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पेलोड़, बृ्ध अध्यक्ष आशीष सोनी, भगवती लाल, प्रतीक वैष्णव, गिरिराज वैष्णव, पुरुषोत्तम योगी, राकेश आचार्य, दिनेश सोनी, माणक चौहान, अशोक शर्मा, जगदीश जाट समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

आयुक्त पर स्याही फेंकी

राजसमंद, (निस्)। शुक्रवार शाम को हुए स्याही कांड ने राजनीतिक मर्यादाओं को शर्मसार कर दिया। बालकृष्ण स्टैडियम में निरीक्षण के दौरान नगर परिषद सभापति अशोक टांक और आयुक्त ब्रजेश राॅय पर स्याही फेंके जाने को घटना से शहर का राजनीतिक माहौल गरमा गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और नगर परिषद कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला।घटना के दौरान नगर परिषद कर्मचारियों ने मौके पर मौजूद भाजपा आईटी सेल संयोजक एवं सांसद प्रवक्ता भरत दवे को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि स्याही फेंकने की वारदात में ४ से ५ अन्य लोग भी शामिल थे, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए भाजपा नेता भरत दवे को डिटेन कर लिया

अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी

राजस्थान का अगले दौर में क्वालीफाई



जयपुर, 19 दिसंबर। राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में बीसीसीआई अंडर 19कूच बिहार ट्रॉफी के जयपुर में खेले जा रहे राजस्थान – जम्मु कश्मीर मैच के अंतिम दिन राजस्थान ने जम्मु एंड कश्मीर टीम को रोमांचक मुक़ाबले में 55 रनोसे हराया। राजस्थान पहली पारी 207 आल आउट।जम्मु पहली पारी 65 आल आउट।राजस्थान दूसरी 335 आल आउट।जम्मु एंड कश्मीर दूसरी पारी 422 आल आउट।आज मैच के अंतिम दिन जम्मु एंड कश्मीर टीम 422 रनो के स्कोर पर आल आउट हो गयी। राजस्थान के गेंदबाजप्रखर शर्मा 95/3, हनी प्रताप सिंह 66/3 केतन देवासी 110/3, जतिन 1 विकेट प्राप्त करते हुए मैच में शानदार जीत दर्ज की व इस जीत के साथ राजस्थान टीम ने प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश किया।

विजय हजारे ट्रॉफी हेतु राजस्थान टीम के संभावितों का शिविर आरसीए अकादमी पर शुरू : बीसीसीआई की आगामी विजय हजारे एक दिवसीय ट्रॉफी में भाग लेने वाली राजस्थान टीम के संभावितों का प्रशिक्षण शिविर आज से आरसीए अकादमी पर शुरू हुआ। प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों ने स्पॉट स्ट्राफ के निर्देशन में कड़ा अभ्यास किया। बीसीसीआई अंडर 16 विजय मर्चेट ट्रॉफी के राजस्थान पंजाब मैच के दूसरे दिन का स्कोर :- पंजाब पहली पारी 156 आल आउट।राजस्थान पहली पारी 129 आल आउट।पंजाब दूसरी पारी 251/8, आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पंजाब ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 251 रन बना लिए थे।टीम के लिए पारस नाबाद 120, साहिबजीतवीर 50 रन।राजस्थान के गेंदबाज हिमांशु जगन्ना 51/4, प्रतीक चौधरी 56/2 व रोहन 1 विकेट। अंडर 19 बीमेन एक दिवसीय ट्रॉफी (राजस्थान – बड़ोदा मैच) बड़ोदा जीती-जिबेंदम में खेली जा रही बीसीसीआई बीमेन एक दिवसीय ट्रॉफी के आज खेले गए राजस्थान – बड़ोदा मैच में बड़ोदा जीती। बड़ोदा पारी 263/8,टीम के लिए आतोशी 78 , विधि 71 रन।राजस्थान की गेंदबाज धृति माथूर 25 / 3 , मैना सियोल 51 / 2 विकेट।राजस्थान पारी 122 आल आउट। टीम के लिए धृति माथूर 34 , प्रियोशी 25 व तनिका मौर 18 रन।बड़ोदा की गेंदबाज नदिनी 3 , स्नेहा , मुन्नि , तन्वी 2 – 2 विकेट।

प्रखर असावा ने सिडको ओपन में 25वां स्थान हासिल किया

जयपुर, 19 दिसंबर। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब के प्रखर असावा ने 16 से 19 दिसंबर 2025 तक खारघर वैली गोल्फ में आयोजित लार्सन एंड टुन्नो नेशनल गोल्फ चैम्पियनशिप के सिडको ओपन में 25वां स्थान हासिल किया। इस पार लॉन्च किए गए अंतरराष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट में शीर्ष भारतीय पेशेवर खिलाड़ियों जैसे मनु गंडास, वीर अहलावत, रोहन ढोले पाटिल के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मिचेल ऑर्टोलानो, सुबाश तामांग, स्टेफन डानेक, एन. थंगराजा, बादल हुसैन और जोशुआ सील जैसी प्रतिभाएं भी शामिल थीं।



तिलक-पंड्या की फिफ्टी: चक्रवर्ती को 4 विकेट

भारत ने लगातार 8वीं टी-20 सीरीज जीती: साउथ अफ्रीका को 5वें मैच में 30 रन से हराया

अहमदाबाद 19 दिसंबर। भारत ने शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 30 रनों से धूल चटाई। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 232 रनों का टारगेट देने का बाद मेहमान टीम को 201/8 के स्कोर पर रोका। भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3–1 से अपने नाम की। लखनऊ में चौथा मुक़ाबला धुंध के कारण रद्द हो गया था। टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। भारत ने पहली बार घर पर साउथ अफ्रीका से टी20 सीरीज जीती है। अहमदाबाद में लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने अच्छा आगाज किया। ओपनर किंटन डिर्कोक और रीजा हेंड्रेक्स ने 69 रन जोड़े। रीजा 12 गेंदों में सात रन बनाने के बाद सातवें ओवर में लौटे। डिर्कोक ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़े। डिर्कोक 11वें ओवर में आउट हुए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की पारी पटरी से उतर गई। उन्होंने 65 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें



9 चौके और तीन सिक्स हैं। इससे पहले, भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन जुटाए। तिलक वर्मा ने भारत के लिए दूसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़े। डिर्कोक 11वें ओवर में आउट हुए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की पारी पटरी से उतर गई। उन्होंने 65 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें

गौतम गंभीर को टीम के कोच की जगह प्रबंधक होना चाहिए: कपिल देव

कोलकाता, 19 दिसंबर। भारत के पहले विश्व कप जीतने वाले कप्तान कपिल देव ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को लेकर कहा कि आज के क्रिकेट सेटअप में गंभीर को कोच के बजाय टीम प्रबंधक के तौर पर देखा जाना चाहिए।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के आईसीसी शताब्दी सत्र में कपिल ने कहा कि समकालीन क्रिकेट में कोच शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है और उन्होंने उच्चतम स्तर पर इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। कपिल की यह टिप्पणी भारत के हाल ही में घर पर टेस्ट सीरीज में 0–2 से हार के बाद गंभीर की बढ़ती आलोचना के बीच आई है, जिसमें खिलाड़ियों के बार-बार रोटेशन और ऑलराउंडरों पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर गंभीर की आलोचना की गई है।

कपिल ने कहा, "आज, कोच नाम का यह शब्द, कोच एक बहुत ही आम शब्द है। गौतम गंभीर कोच नहीं हो सकते। वह टीम के मैनेजर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप कोच कहते हैं, तो आपको वह होता है जिनसे मैं स्कूल और कॉलेज में सीखता हूं।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि गौतम गंभीर किसी लेग-स्पिनर या विकेटकीपर को क्रिकेट की बारीकियां कैसे



सिखा सकते हैं। उनके अनुसार, यह काम स्कूल या कॉलेज स्तर के कोचों का होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कोच का असली काम खिलाड़ियों के व्यक्तित्व को समझना, उनका मनोबल बढ़ाना और टीम के लिए एक सही माहौल तैयार करना है।" पूर्व ऑलराउंडर ने इस बात पर बल दिया कि कोच का काम तकनीकी सिखाने से ज्यादा खिलाड़ियों का सही तरीके से प्रबंधन करना होता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आपको मैनेज करना होगा। यह अधिक महत्वपूर्ण है। एक प्रबंधक के तौर पर आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि आप यह कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रबंधक बनते हैं, तो युवा लड़के आपको देखते हैं।"

कपिल ने समझाया कि एक सहायक

माहौल बनाना कप्तान और टीम मैनेजमेंट दोनों का एक प्रमुख जिम्मेदारी थी।

उन्होंने कहा, "अप किसी लेगस्पिनर या विकेटकीपर को कैसे कोच कर सकते हैं, जब वे पहले से उस कला में माहिर हैं? ऐसे में सबसे जरूरी काम मैनेजमेंट का होता है। एक मैनेजर खिलाड़ियों को भरोसा देता है, हौसला बढ़ाता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे बेहतर कर सकते हैं।" कपिल ने कहा, "कप्तान या प्रबंधक का काम टीम को आराम और आत्मविश्वास देना है। खासकर उन खिलाड़ियों को, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं।" उन्होंने अपने कप्तानी अनुभव को साझा करते हुए कहा, "जो खिलाड़ी शतक बनाता है, उसके साथ मैं डिनर नहीं जाऊंगा। मैं उन लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद करता हूं, जो संघर्ष कर रहे हों, ताकि उन्हें आत्मविश्वास मिले।" (नाबाद 61) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने शुक्रवार को अंडर-19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका को 12 गेंद शेष रहते आठ विकेट में जगह बना ली है जहां उसका मुक़ाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा।। 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने

उन्होंने कहा, "इसलिए मुझे लगता है कि एक कप्तान के तौर पर यह बहुत जरूरी है, और आपकी भूमिका केवल आपका प्रदर्शन नहीं है, बल्कि टीम को एक साथ लाना भी है।"

राजधानी

राजस्थान रिफाइनरी इकाई का 96.4 प्रतिशत कार्य पूर्ण

मूंदड़ा पोर्ट पहुंची अरब मिक्स क़ूड ऑयल की पहली खेप, मेहसाना भटिण्डा गैस पाइपलाईन से गैस आना शुरू

जयपुर (कास)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में एचआरआरएल की राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की 7 वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के साथ ही देश की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें रिफाइनरी के साथ ही पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स भी है। उन्होंने रिफाइनरी के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों पर परस्पर समन्वय से कार्य करते हुए रिफाइनरी का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विस्तार से प्रगति और संबंधित बिन्दुओं की जानकारी ली।



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को एचआरआरएल की राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की 7वीं बैठक आयोजित हुई।

दासगुप्ता ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी (एचआरआरएल) कार्य प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि रिफाइनरी का समग्र रूप से 90.3 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है जिसमें रिफाइनरी इकाई का 96.4 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है वहीं रिफाइनरी के लिए मूंदड़ा पोर्ट पर अरब मिक्स से कूड टैंक (सीओटी) तक

रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की पहली खेप आ गई है और यह मूंदड़ा पोर्ट के 6 टैंकों से पाइपलाईन के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचेगी। रिफाइनरी में ओबीई कार्य 99.8 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

सीएमडी एचपीसीएल विकास कौशल ने बताया कि राजस्थान सरकार के सहयोग व समन्वय से रिफाइनरी

छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया, परंतु शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य विवि और कॉलेजों में तुरंत छात्रसंघ चुनाव कराने के संबंध में निर्देश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन इसे शिक्षा के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर एक स्पष्ट और तर्कसंगत नीति बनाई जानी चाहिए। अदालत ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि वह अपने चुनाव को लेकर पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था रखें और यह सुनिश्चित करें कि इस दौरान शैक्षणिक कामकाज प्रभावित नहीं हो। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जय राव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

अदालत ने कहा कि फिलहाल मौजूदा शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के अंतिम चरण में है और ऐसे में इस शैक्षणिक सत्र में छात्रसंघ चुनाव के लिए अदालत कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहता। अदालत ने कहा कि 19 जनवरी, 2026 को सभी विवि और कॉलेजों सहित अन्य संबंधित लोगों की बैठक बुलाई जाए। इस बैठक में भविष्य के छात्रसंघ चुनावों के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए जाए। वहीं यदि चुनाव नहीं कराने के संबंध में निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए ठोस और तार्किक कारण बताए जाने चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार व यूनिवर्सिटी को कहा है कि वे चुनावों के सही तरीके से संचालन के लिए एक छात्रसंघ चुनाव बोर्ड या समिति गठित करें, जो इन चुनावों के लिए जवाबदेह हो। अदालत ने कहा कि चुनाव कैलेंडर हर शैक्षणिक वर्ष के माच महीने में जारी किया जाए।

■ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा “संबंधित विभाग समन्वय से रिफाइनरी का कार्य पूरा करें”

■ एचआरआरएल रिफाइनरी राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट

■ राजस्थान रिफाइनरी का समग्र रूप से 90.3 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका

कार्य प्रगति पर है। रिफाइनरी में मेहसाना भटिण्डा गैस पाइपलाईन (एमबीपीएल) से गैस आना शुरू होने के साथ ही प्लेयर सिस्टम शुरू होने से टेस्टिंग प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी के नाचाने रिजर्व वायर से पाइपलाईन से पानी आने लगा है। टी. रविकान्त ने बताया कि पेट्रोलीयम विभाग द्वारा लगातार समन्वय बनाते हुए रिफाइनरी को गति दी जा रही है।

आरयूएचएस में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी शुरू

जयपुर । आरयूएचएस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार एवं नेतृत्व में प्रदेश के डेयरी क्षेत्र नेगत 2 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 2 सालों में लगभग 5 लाख किसानों को 1172 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों के लिए सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के तहत 3 लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जा रही है। अब तक लगभग 34 हजार दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जा चुका है। राज सरकार द्वारा सरस मायरा योजना शुरू की गई है। इसके तहत दुग्ध उत्पादक सदस्यों की बेटी को शादी में 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

राजस्थान रिफाइनरी की खास बात यह है कि जो लिक्विड इफ्टएंट डिस्चार्ज है जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इस रिफाइनरी में प्रसंस्करण के दौरान किसी तरह का वेस्टेज नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बालोतरा से पचपदरा 12 किमी तक रेल्वे व पचपदरा से रिफाइनरी साइट तक एचआरआरएल द्वारा रेल्वे बालोतरा बिछाई जाएगी। रिफाइनरी से प्रदेश में निवेश, रोजगार और रवेन्यू ने नए

राजस्थान में दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में पांच लाख किसानों को मिला 1172 करोड़ रु. अनुदान

जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के डेयरी क्षेत्र नेगत 2 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 2 सालों में लगभग 5 लाख किसानों को 1172 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों के लिए सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के तहत 3 लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जा रही है। अब तक लगभग 34 हजार दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जा चुका है। राज सरकार द्वारा सरस मायरा योजना शुरू की गई है। इसके तहत दुग्ध उत्पादक सदस्यों की बेटी को शादी में 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

अवसर होंगे। बैठक में बालोतरा से रिफाइनरी तक रेल्वेलाईन बिछाने, बिजली सबस्टेशन, राज्य से आने वाले कच्चे तेल पर वेट कम करने सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर राजस्थान रिफाइनरी की एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।टास्क फोर्स की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव व चेयरमेन आईजीएसपी अभय कुमार, प्रमुख सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा, वित्त वैभव गालरिया, राजस्व सचिव जोगानाम, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, रीको, उत्तर पश्चिम रेल्वे, एमओपीएस, कलेक्टर बालोतरा, संभागीय आयुक्त, आरएसएमएमएल, संयुक्त निदेशक डेयरी क्षेत्र में कुशल और प्रभावी प्रबंधन तथा संसाधनों के समुचित उपयोग के फलस्वरूप वर्षों से घाटे में चल रही 15 दुग्ध इकाइयों वर्तमान में मुनाफा दे रही है।

